बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 122

## धनाढ्यों पर कर

**वित्त** मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करने के दौरान शुरुआत में ही यह कह कर एकदम उचित किया कि सरकार वैध तरीके से लाभ अर्जित करने को खराब नहीं मानती। यह स्वागत योग्य टिप्पणी थी। देश में कारोबारी जगत बहुत लंबे समय तक लाइसेंस राज का शिकार रहा और पैसे कमाने को हमेशा अच्छा नहीं माना गया। उन्हें यह श्रेय भी मिलना चाहिए कि उन्होंने कम कॉर्पोरेट कर दर का लाभ 0.7 फीसदी कंपनियों को छोड़कर शेष तक पहुंचाया, हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि यह सबको मिलेगा।

परंतु इस घोषणा का सुखद प्रभाव बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रहा क्योंकि मंत्री ने 2 करोड़ रुपये से अधिक आय अर्जित करने वाले करदाताओं पर अधिभार बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए प्रभावी कर दर में क्रमश: 3 और 7 फीसदी का इजाफा होगा। प्रस्ताव करदाताओं के एक छोटे तबके को ही प्रभावित करेगा लेकिन यह विचार कई स्तरों पर गड़बड़ है और इससे बचा जाना चाहिए था। अनुमान है कि आय कर संग्रह में 3,000 करोड़ रुपये से भी कम इजाफा होगा। व्यापक तौर पर देखा जाए तो यह कर ढांचे को सरल बनाने के मूल विचार के ही खिलाफ है। हालांकि अतीत में भी कई तरह के उपकर और अधिभार लगाए गए हैं लेकिन इस बजट में यह काम अलग ही स्तर पर हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक कारणों से इन्हें पलटना भी संभव नहीं होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ऐसी व्यवस्था को बदलना क्यों चाहती है जो लंबे समय से लागू है। अनुभव बताता है कि जब दरें कम रहती हैं तो संग्रह बढ़ने की आशा रहती है।

यह बात भी सर्व स्वीकार्य है कि सरकार को सामाजिक दायित्व पूरा करने के क्रम में राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में संग्रह बढ़ाने के लिए अनुपालन और कर दायरा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि लोगों को कर चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और कर प्रशासन को सुधार कर अनुपालन न होने की घटनाओं का पता लगाया जा सके। हालांकि अनुपालन और प्रशासन के मोर्चे पर कुछ प्रगति देखने को मिली है लेकिन रियायतों और छूट की सीमा की नियमित समीक्षा ने कर आधार में सार्थक बढ़ोतरी की संभावनाओं को सीमित किया है। उदाहरण के लिए अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले करदाताओं को पूरी छूट दी गई थी। इसका राजस्व प्रभाव 18,000 करोड़ रुपये से अधिक था। वांछित यह है कि कम तादाद वाले करदाताओं से अधिक राशि वसूलने के बजाय ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां ढेर सारे लोग थोड़ा-थोड़ा कर चुकाएं। इतिहास बताता है कि उच्च कर दर कर वंचना को जन्म देती है। संभव है कि अत्यधिक अमीर तबका अपना कर दायित्व कम करने की राह तलाश करे। यह देखना दिलचस्प होगा कि नए अधिभार के बाद वास्तविक संसाधनों में क्या तब्दीली आती है। इसके अलावा अगर सरकार मानती है कि अमीरों को अधिक योगदान करना चाहिए तो उसे कर स्लैब में संशोधन करना चाहिए। इससे ढांचा सहज और पारदर्शी बना रहेगा तथा राज्यों को भी उचित हिस्सेदारी मिलेगी। दरअसल सरकार ने नई प्रत्यक्ष कर संहिता पर काम कर रहे पैनल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आशा की जानी चाहिए कि पैनल प्रत्यक्ष करों को सहज बनाने की अनुशंसा करेगा और सरकार इससे संतुष्ट होगी। उच्च वृद्धि दर हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में एक स्थिर, सहज और ऐसी कर व्यवस्था हो जिसके बारे में अनुमान लगाना आसान हो।

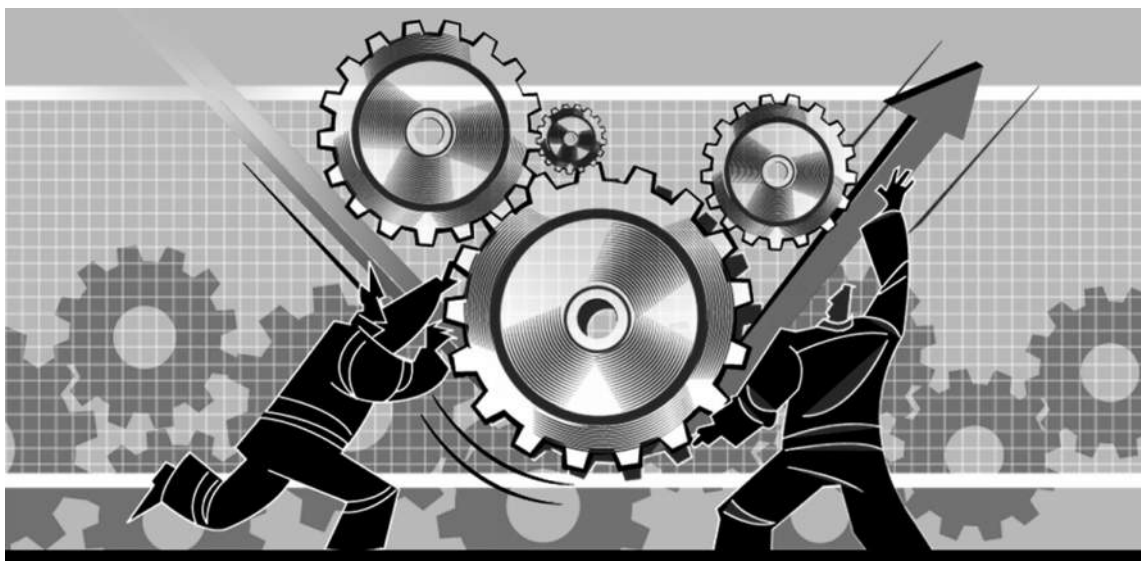

अजय मोहंती

# आर्थिक वृद्धि में तेजी के लिए रणनीतिक कदम

### विनिर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्यात केंद्रित पश्चगामी एकीकरण रणनीति आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए जरूरी है। बता रहे हैं **नितिन देसाई**

आर्थिक समीक्षा और बजट भाषण दोनों में आर्थिक वृद्धि दर को मौजूदा 6-7 फीसदी दायरे से आगे ले जाने की जरूरत पर बल दिया गया है। अगले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य अब साफ तौर पर आर्थिक नीति के केंद्र में है। लेकिन इस लक्ष्य के लिए जरूरी 10-11 फीसदी वृद्धि दर विनिर्मित उत्पादों के उत्पादन एवं विनिमेय सेवाओं में खास तेजी लाए बगैर संभव नहीं है। इसके साथ ही ढांचागत क्षेत्र, पूंजी बाजार और श्रम गतिशीलता में भी जबरदस्त सुधार लाने की जरूरत होगी।

वृहद स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी करीब चार दशकों से 17 फीसदी के आसपास टिकी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विनिमेय सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। कुल मिलाकर तैयार उत्पाद बनाने वाले उद्योगों का हिस्सा बुनियादी सामग्री के बरक्स बढ़ा है। विनिर्माण उद्योगों में वृद्धि तेज हो सकती है अगर मांग में वृद्धि होती है। घरेलू उपभोग की मांग आर्थिक वृद्धि का वाहक नहीं हो सकता है क्योंकि इसके त्वरित वृद्धि का कारण होने के बजाय उसका नतीजा होने की अधिक संभावना है। इस साल के बजट में नए सिरे से समर्थित आयात प्रतिस्थापन की पुरानी नीति की सीमित संभावना है और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता की मंशा पर चोट करता है। हालांकि हमारी बड़ी जरूरतों को देखते हुए रक्षा या मेट्रो रेल जैसी ढांचागत परियोजनाओं या सार्वजनिक सेवा के डिजिटल नेटवर्क के लिए उन्नत उपकरणों की सार्वजनिक खरीद कुछ परिष्कृत इंजीनियरिंग उद्योगों में वृद्धि को रफ्तार दे सकती है, अगर खरीद का फैसला करने वालों का लंबी अवधि का नजरिया हो। हालांकि अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव कम होगा और बाहरी मांग में व्यापक तेजी विनिर्माण निर्यात एवं विनिमेय सेवाओं की वृद्धि का नतीजा होनी चाहिए।

आर्थिक समीक्षा तीव्र वृद्धि को लेकर चीन के रिकॉर्ड का जिक्र करती है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र की निर्यात-केंद्रित वृद्धि ने अहम योगदान दिया था। वृद्धि रणनीति को लेकर चीन और कुछ पूर्व-एशियाई देशों के दृष्टिकोण को निर्यात-केंद्रित बैकवर्ड इंटिग्रेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल कंपनी के सक्रिय प्रवर्तन में संचालित हो रही घरेलू कंपनियों ने आयातित तकनीक, उपकरणों एवं माल के सहारे उच्च वृद्धि वाले निर्यात-योग्य उत्पाद बनाने से लेकर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले इनपुट उत्पादों के विनिर्माण की भी क्षमता हासिल कर ली। तकनीकी विकास का स्वदेशीकरण मुख्य रूप से मूल कंपनियों के रास्ता दिखाने से ही संभव हो पाया।

भारत में ऐसा नहीं हुआ है। मसलन, हमारे दवा उद्योग का निर्यात काफी तेजी से बढ़ा है। लेकिन यह अब भी काफी हद तक चीन से आयात किए जाने वाले रसायनों पर ही आश्रित है। हालिया उदाहरण स्मार्टफोन उद्योग का है जो भारत में असेंबलिंग गतिविधि भर ही है। निर्यात के मोर्चे पर सफल एक और क्षेत्र सॉफ्टवेयर सेवा है। लेकिन इसमें आंशिक बैकवर्ड इंटिग्रेशन ही हुआ है और कृत्रिम मेधा एवं मशीन लर्निंग जैसे अग्रिम क्षेत्रों में तो बहुत कम हुआ है।

भारत पूर्व एशियाई देशों का उदाहरण अपना सकता था और उसने ऑटो क्षेत्र में यह किया भी था लेकिन वह बढ़ती घरेलू मांग का नतीजा था निर्यात का नहीं। जब 1980 के शुरुआती दशक में मारुति आई तो उसने सुनिश्चित खरीद, वित्त एवं तकनीकी मदद के व्यवस्थित तरीके से कल-पुर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया था। आज भारत में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी ऑटोमोबाइल एवं उपकरण उद्योग हैं जो एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर उभरा है।

हम इस नजीर को दोहराने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? बैकवर्ड इंटिग्रेशन के लिए प्रोत्साहन देने वाली निर्यात-केंद्रित रणनीति एक नवजात उद्योग रणनीति से खासी अलग है क्योंकि इसमें सक्षमता एवं लागत कटौती के लिए अंतर्जात दबाव होता है।

निर्यात-केंद्रित रणनीति इन चार बातों की प्रचुरता पर निर्भर करती है। गैर-विनिमेय इनपुट खासकर ढांचागत सेवाओं की सक्षम आपूर्ति, जरूरी कौशल रखने वाले श्रमिकों की उपलब्धता, खरीद क्षमता अनुरूपता एवं उत्पादकता में परिवर्तन के अनुरूप विनिमय दर और तकनीकी गतिशीलता की प्रचुरता मायने रखती है।

बिजली, परिवहन और संचार जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता आज के समय में विनिर्माण निवेश के लिए बड़ी समस्या नहीं रह गई है। असली समस्या कारोबार सहूलियत और व्यापार नीति-निर्माण, मंजूरियां, सीमा नियंत्रण और कर प्रशासन के प्रशासनिक ढांचे से है। उदाहरण के तौर पर जीएसटी रिफंड में निर्यातकों को आ रही दिक्कतों को देख सकते हैं।

जरूरी कौशल रखने वाले श्रमिकों की उपलब्धता अहम है लेकिन यह निर्यात अवसरों का फायदा उठाने की पूर्व-शर्त नहीं है। जब मौके आते हैं तो रोजगार की तलाश करने वाले लोग अपने पैसे लगाकर संबंधित कौशल हासिल कर लेते हैं। कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर कोडिंग के क्षेत्र में निर्यात संभावनाएं बढ़ने के समय हम ऐसा देख चुके हैं। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देने पर अपेक्षाकृत कम लागत आती है और इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कौशल की कमी निर्यात वृद्धि में अवरोधक न बने। हालांकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण का एक बुनियादी स्तर होना जरूरी है और वह तैयार भी किया जा चुका है। फिर भी हमारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में प्राइमरी स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापरक सुधार लाने की जरूरत है।

विनिमय दर प्रबंधन भी महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2002-03 और 2011-12 के बीच भारत का गैर-तेल निर्यात पांच गुना बढ़कर 50 अरब डॉलर से 250 अरब डॉलर हो गया। उसके बाद से गैर-तेल निर्यात का डॉलर मूल्य कम होता गया है। निर्यात-संवर्द्धित वास्तविक विनिमय दर उच्च वृद्धि के दौरान 2004-05 के स्तर पर कमोबेश स्थिर थी। लेकिन उसके बाद से वास्तविक विनिमय दर बढ़ने से निर्यात कम प्रतिस्पर्द्धी हो गया है और धीमे विकास के लिए यह भी आंशिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए।

ये तीनों कारक मध्यम अवधि के लिए अहम हैं लेकिन दीर्घावधि में विनिर्माता एवं कारोबारी सेवाओं के निर्यात के लिए कंपनी एवं देश के स्तर पर तकनीकी क्षमता रखना सबसे ज्यादा मायने रखता है। तकनीकी गतिशीलता उत्पादकता बढ़ाने वाले कारक या ऊर्जा और माल उत्पादकता में सुधार से कहीं अधिक है। इसमें शूम्पीटर के आर्थिक सिद्धांत का वह पहलू भी शामिल हो जो नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, व्यवसाय प्रवृतियों के रूप में लागू नवाचारों की दर और नए बाजारों के विकास की दर का जिक्र करता है।

बाह्य बाजार-उन्मुख विकास रणनीति तकनीकी गतिशीलता पर दोनों तरह से दबाव डालती है। कीमत को प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने की जरूरत के चलते संसाधन सक्षमता में सुधार और विकसित होते वैश्विक बाजारों में प्रासंगिक बने रहने के लिए नए उत्पादों एवं प्रक्रिया के नवाचारी विकास के लिए तकनीकी गतिशीलता। कमतर विनिमय दर से मदद मिल सकती है और अधिमूल्य वाली विनिमय दर कीमत प्रतिस्पर्द्धा को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन एक वैश्विक बाजार में प्रवेश और वहां टिके रहने के लिए दोनों ही संभावनाएं बेहद कम गुणवत्ता मानकों और नवाचार के जरिये इनमें किए जाने वाले बदलावों पर निर्भर करेगा।

निर्यात-केंद्रित बैकवर्ड इंटिग्रेशन रणनीति की राह में सबसे बड़ी बाधा नीति बनाने का वह तरीका है जिसमें नए सिरे से डिजाइन साधनों के बजाय बड़े लक्ष्यों पर जोर दिया जाता है। आर्थिक वृद्धि की कारगर नीतियां साध्य के बजाय साधनों पर अधिक बल देती हैं।

# सुविचारित ढंग से तैयार किया गया राजनीतिक बजट

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

**इस बजट को भारत समर्थक बजट के रूप में प्रस्तुत करना भाजपानीत केंद्र सरकार का एक राजनीतिक कदम है। हकीकत इससे अलग है।**

**वित्त** मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत शुक्रवार को जो केंद्रीय बजट पेश किया, उसके बारे मे कहा गया कि उसके केंद्र में ग्रामीण भारत था। उन्होंने 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा 'हम जो कुछ करते हैं, उसके केंद्र में हम गांव, गरीब और किसान को रखते हैं।' उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी चिंता के केंद्र में इंडिया नहीं बल्कि भारत है जो ग्रामीणों, किसानों और गरीबों से बना है। क्या उनके बजट के आंकड़े ग्रामीण भारत के लिए बनी योजनाओं का वित्तीय आवंटन बढ़ाकर उस चिंता को दूर करने का प्रयास करते दिखते हैं?

ग्रामीण विकास का उदाहरण लें तो यह किसानों, गांवों और गरीबों की चिंता का विषय है। परंतु 2019-20 के बजट में इस क्षेत्र के आवंटन में महज 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 1.41 लाख करोड़ रुपये किया गया है। यह इस वर्ष बजट व्यय में हुए कुल 13 फीसदी के इजाफे की तुलना में बहुत कम है। ग्रामीण विकास के अधीन भी सबसे बड़ा व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में होता है लेकिन इस वर्ष इस मद में केवल 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो एक वर्ष पहले के 61,084 करोड़ रुपये से कम है।

नवगठित जलशक्ति मंत्रालय के बारे में वित्त मंत्री के भाषण के दो बड़े पैराग्राफ थे। इस मंत्रालय में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनर्जीवन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय आदि विभाग शामिल हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि कैसे पाइप से जलापूर्ति सरकार का लक्ष्य है और वह जल संसाधनों के संरक्षण और गंगा के पुनर्जीवन के लिए काम करेगी। परंतु नवगठित मंत्रालय के बजट में चालू वर्ष के लिए 28,262 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई जो वर्ष 2018-19 में इस मद में किए गए व्यय से केवल 2 फीसदी अधिक है। अगर जल शक्ति इतना बड़ा मिशन था तो इसके लिए और अधिक संसाधन क्यों नहीं आवंटित किया गया?

कृषि और संबद्ध गतिविधियों में यह रुझान बदला हुआ प्रतीत होता है। वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन 75 फीसदी बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। परंतु यह बढ़ोतरी मोटे तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और किसानों की पेंशन योजना में बढ़ाई गई है। वर्ष के लिए 64,916 करोड़ रुपये में से 55,000 करोड़ रुपये की राशि पीएम किसान योजना में और 900 करोड़ रुपये की राशि किसानों की पेंशन के लिए है। दूसरे शब्दों में कहें तो अन्य कृषि योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केवल 9,000 करोड़ रुपये की राशि बढ़ाई गई। इसमें बहुप्रतीक्षित शोध परियोजनाएं भी शामिल हैं।

इससे सरकार की यह मान्यता सामने आती है कि किसानों की जरूरत मोटे तौर पर आय हस्तांतरण और पेंशन योजना से पूरी हो जाएगी। गत वर्ष सरकार ने पीएम किसान योजना पर 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस वर्ष यह बढ़कर 75,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। यहां प्रावधान में कमी नजर आती है। सरकार ने पीएम-किसान योजना का विस्तार कर सभी किसानों को उसमें शामिल करने का निर्णय किया है। ऐसे में इस मद में 87,000 करोड़ रुपये का प्रावधान होना था। क्या किसान पेंशन योजना में केवल 900 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त होगी?

ध्यान रहे कि बजट भाषण में ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित करना एक राजनीतिक कदम है जिसे बेहद सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। मोदी सरकार शहरी या अमीर वर्ग के बजाय ग्रामीण भारत के हित में काम करती हुई दिखना चाहती है। बहरहाल, ग्रामीण विकास या जल संसाधन के लिए किया गया मामूली आवंटन बजट में उल्लिखित प्रतिबद्धता का समर्थन नहीं करते। मोदी सरकार की भारत समर्थक छवि को मजबूत करने में अमीरों पर कर में इजाफे और घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए टैरिफ बढ़ाने जैसी बातें अधिक अहम हैं।

यही बात इस बजट को अलग बनाती है। यह चतुराईपूर्वक तैयार किया गया दस्तावेज है जो बजट समर्थक नीतिगत पैकेज के बीच देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी के लिए और अधिक खोलता है और निजीकरण तथा रेलवे आदि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने जैसे सुधारों की जमीन तैयार करता है।

बजट पर होने वाली चर्चा जहां भारत से जुड़ी प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित है वहीं वित्तीय आवंटन में बिना समुचित इजाफे के, अमीरों पर कर बढ़ा कर और तीन दर्जन से अधिक वस्तुओं के आयात शुल्क में बढ़ोतरी करके घरेलू उद्योग के लिए समान माहौल तैयार करने की कोशिश के साथ बजट में कई नई पहल की गई हैं। इनमें बाहरी बाजारों से उधार लेना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के मानक शिथिल करना तथा सरकारी उपक्रमों में सरकार की शेयर हिस्सेदारी को 51 फीसदी से कम करना शामिल हैं।

इस बजट को भारत समर्थक बजट के रूप में प्रस्तुत करना भाजपानीत केंद्र सरकार का एक राजनीतिक कदम है। हकीकत इससे अलग है। यह ऐसा बजट है जो नए क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का प्रवेश, निजीकरण और नए सहज श्रम कानून आदि की राह आसान करता है। बजट को भारत समर्थक दिखाने का मुल्लमा जानबूझ कर पहनाया गया है ताकि आर्थिक खुलेपन को नकारने की किसी भी तरह की राजनीतिक कोशिश को रोका जा सके।

## कानाफूसी

### औचक निरीक्षण

अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको लोगों को सक्रिय रखना होगा। राज्य के अफसरशाहों के साथ अपनी शुरुआती मुलाकातों में से एक में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने उनसे कहा कि वे विभिन्न सरकारी संस्थानों में रात को औचक रुकने का कार्यक्रम बनाएं ताकि उनकी सेवा गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे छात्रावासों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में जाएं, वहां की कैंटीन में भोजन करें और यदि संभव हो तो रात में वहीं सो जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि वे किसी से अपनी योजना के बारे में चर्चा न करें और नियमित अंतराल पर संस्थानों का औचक निरीक्षण करना जारी रखें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से इन संस्थानों को चलाने वाले लोग कभी ढिलाई नहीं बरतेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें संस्थानों में अंतर नजर आने लगे तो 'तब और अब' की तस्वीरें भी खींच कर रखें।

### आदित्य का उदय

शिव सेना की युवा इकाई युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इंडियन पॉलिटिकल ऐक्शन कमेटी (आई-पैक) की सहायता लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उनके पिता उद्धव ठाकरे और परिवार के अन्य राजनीतिक रूप से सक्रिय सदस्यों ने भी उनके इस कदम का समर्थन किया है। यात्रा का लक्ष्य न केवल उनकी लोगों तक पहुंच आसान करना है बल्कि उन्हें भविष्य के संभावित मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सामने पेश करना भी है। आदित्य महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों की यात्रा करेंगे और विभिन्न सत्रों में भागीदारी करेंगे जहां कॉलेज के युवाओं और कामकाजी युवाओं के साथ सवाल जवाब किया जाएगा।

## आपका पक्ष

### देश में जीरो बजट खेती का सुझाव

देश में कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन तथा जल की कमी से जूझ रहा है। रासायनिक खेती महंगी होती है और यह जमीन की उत्पादक क्षमता कम कर देती है। रासायनिक युक्त खाद्य मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वजह से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसलिए केंद्र एवं राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कृषि सुधार के लिए कदम उठा रही हैं। सरकार के समक्ष देश की 136 करोड़ से अधिक आबादी को अनाज मुहैया कराने का दायित्व है। लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ती दर पर अनाज भी उपलब्ध कराना है। सरकार ने विगत दिनों जैविक खेती को अधिक महत्त्व दिया है जिसके परिणामस्वरूप सिक्किम पूरी तरह जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बना है। लेकिन जैविक खेती खर्चीली है और इसकी उत्पादन क्षमता उम्मीद से कम है। इसके अलावा जैविक फसल की कीमत भी अधिक होने से केवल

विशेष वर्ग के लोग ही इसे खरीद पाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने अपने बजट सत्र में जीरो बजट खेती की संकल्पना पेश की है। विदर्भ के एक किसान ने कुछ वर्ष पूर्व जीरो बजट खेती की संकल्पना पेश की थी। यह खेती पूरी तरह से प्राकृतिक होती है जो देसी गाय के गोबर से बनी खाद पर आधारित है। एक देसी गाय की गोबर खाद

**किसानों को जैविक खेती पर जोर देना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल है**

एवं गोमूत्र से एक किसान 30 एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है। देसी गाय के गोबर का खेत में उपयोग करने से मिट्टी के पोषक तत्त्वों में वृद्धि होती है तथा जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। यह मुफ्त में मिल जाता है इसलिए यह महंगे खाद का एक बेहतर विकल्प है। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरकता भी कम नहीं होती है। इसलिए इसे जीरो बजट खेती नाम दिया गया है। सरकार ने इस खेती को मान्यता दे दी है। किसानों के मुताबिक यह खेती ग्लोबल वार्मिंग एवं वायुमंडल में आने वाले बदलाव का मुकाबला करने में सक्षम है। यह किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी मददगार है। अब तक देश के करीब 40 लाख से ज्यादा किसान इस विधि से जुड़े हैं। कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित एवं किसान की दशा सुधारने के लिए आधुनिक एवं पारंपरिक तरीकों को अमल में लाना जरूरी है। इसलिए सरकार का यह कदम सराहनीय एवं स्वागतयोग्य है।

*निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर*

### महिला वित्त मंत्री से महिलाओं को उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले शुक्रवार को संसद में बजट पेश किया। एक महिला वित्त मंत्री से देश की महिलाओं को बड़ी आस थी जिसे शायद वित्त मंत्री ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। बजट में महिलाओं पर आधारित योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है। इस बार के बजट में 1.37 लाख करोड़ रुपये आवंटन किया गया है जो पिछले साल 1.22 लाख करोड़ रुपये था। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया कोष के तहत 891.23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। गरीब परिवारों को एलपीजी उपलब्ध कराकर महिला उत्थान के लिए 2,724 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी अधिक राशि दी जाएगी। बजट में महिला सशक्तीकरण पर भी जोर दिया गया है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।